percent seats reserved for them.The year-wise split up is as under:—

Year	Number of children
1993-94	21
1994-95	10
1995-96	10

9. The Government of Punjab intends to continue to import training to the terrorist affected women and to grant employment under the exsiting schemes on priority basis during the next three years also.

Report on India by Trade Development Board, Singapore

845. SHRI RAM NATH KOVIND: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether attention of Government has been drawn to certain reports which appeared on 20th June, 1996 indicating Singapore's Trade Development Board New Plan for India advocating a focus on regional growth areas, instead of concentrating all investment in one area or well established regions;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government propose to take some initiatives in this regard for implementation of plan of Singapore;

(d) if so, details thereof; and

(e) if not, reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI BOLLA BULLI RAMAIAH): (a) and (b) Although a report regarding Singapore's Trade Development Board New Plan for India has appeared in the Press, no official communication nor the details of such a Plan have been received from the Singapore Trade Development Board.

(c) to (e) Do not arise.

सरकारी-क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्यालय

846. **श्री जनार्दन यादव:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सरकारी-क्षेत्र के ऐसे अनेक उपक्रम हैं जिनकी उत्पादन इकाइयां तो देश के विभिन्न भागों में स्थापित हैं किन्तु उनके मुख्यालय दिल्ली में स्थित हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उपक्रमों के नाम क्या-क्या हैं;

(ग) क्या इन उपक्रमों के प्रशासनिक कार्य में सुधार करने हेतु उनके प्रशासनिक मुख्यालयों का उत्पादन इकाइयों के समीप स्थित होना आवश्यक नहीं है;

(घ) क्या सरकार ने वर्ष 1996 में इन कार्यालयों को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था;

(ङ) कितने कार्यालयों को पहले ही स्थानांतरित किया जा चुका है; और

(च) शेष कार्यालयों को स्थानांतरित न किये जाने के क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोलीमारन): (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के 21 उत्पादनकारी/विनिर्माणकारी उद्यम ऐसे हैं जिनके मुख्यालय दिल्ली में स्थित हैं जबकि उनके उत्पादनकारी एकक देश के विभिन्न भागों में अवस्थित हैं। इन उपक्रमों के नाम विवरण में दिए गए हैं (नीचे देखिए)। चूंकि इन उद्यमों के उत्पादन तथा प्रचलन संबंधी अन्य कार्यकलाप देश के विभिन्न भागों में फैले हुए हैं। इसलिए इनके द्वारा यह वांछनीय समझा गया है कि मुख्यालय ऐसे केन्द्रीय स्थल पर स्थित हों जहां से कारगर नियंत्रण संभव हो सके।

(घ) से (च) राजधानी के शहर को भीड़-भाड़ से मुक्त करने संबंधी उपाय के तौर पर सरकार ने वर्ष 1986 में, न कि 1996 में सरकारी क्षेत्र के कुछेक उन उपक्रमों का निर्धारण किया जिन्हें दिल्ली से बाहर स्थानांतरित किया जाना था। इनमें से चार उद्यमों ने अपना कार्यालय स्थानांतरित कर लिया है जबकि अन्य प्रशासनिक/प्रचालनात्मक कारणों से ऐसा नहीं कर सके है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के ऐसे उपक्रम जिनकी उत्पादन इकाइयां देश के विभिन्न भागों में स्थित हैं किन्तु उनके मुख्यालय दिल्ली में हैं

क्र० सं०	सरकारी उपक्रम का नाम
1.	भारत एल्युमिनियम कम्पनी लि०
2.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०
3.	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि०
4.	भारतीय उर्वरक निगम लि०
5.	भारतीय गैस प्राधिकरण लि०
6.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि०
7.	हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि०
8.	हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयल कारपो० लि०
9.	इंडियन आयल कारपोरेशन लि०
10.	इंटेलीजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लि०
11.	माडर्न फूड इंडस्ट्रीज इंडिया लि०
12.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०
13.	नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपो० लि०
14.	राष्ट्रीय बीज निगम लि०
15.	नेशनल टेक्सटाईल कारपोरेशन लि०
16.	नेशनल थर्मल पावर कारपो० लि०
17.	नेटेका (दिल्ली, पंजाब एवं राजस्थान) लि०
18.	आयल इंडिया लि०
19.	ओएनजीसी (विदेश) लि०
20.	भारतीय राज्य फार्म्स निगम लि०
21.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०

लघु उद्योग क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाया जाना

847. **श्री राम जेठमलानी:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार लघु उद्योग क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश का अंशदान 24 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या लघु उद्योग क्षेत्र में देश की बड़ी-बड़ी कम्पनियों का अंशदान भी 24 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दिये जाने पर विचार किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि लघु उद्योग क्षेत्र सहित सहकारी समितियों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि बड़ी-बड़ी कम्पनियों की भागीदारी का अंश बढ़ने के कारण लघु क्षेत्र के उद्योगों द्वारा किये जाने वाले उत्पादन में अपनायी जा रही विद्यमान श्रम-प्रधान तकनीक के स्थान पर पूंजी प्रधान तकनीक को अधिक बल मिलेगा; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

Underpriced Wheat Export

848. DR. D. VENKATESHWAR RAO: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether India have lost about Rs. 3.00 crore in foreign exchange owing to underpriced wheat export during the last one year;

(b) if so, whether country has exported around 1 million tonne of non-durum wheat against an approved 2.5 MT by the Government last year;

(c) whether exports were made at prices nearly US$ 60 to US$ 100 per MT less than international prices;

(d) if so, main reasons and whether any enquiry was conducted;

(e) if so, the action taken against those held responsible; and

(f) steps being taken to see that loss is not increased during 1996-97?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI BOLLA BULLI RAMAIAH): (a) to (c) During 1995-96, 617211 MTs of wheat valued at Rs. 360.90 crores at a unit price realisation of Rs. 5847.27 per MT (US$ 175.27 per MT, conversion rate 1 $= Rs. 33.36) was exported. It is, however, not possible to accurately compare the prices prevailing in the international and domestic markets on account of different varieties traded,